किया जा रहा था कि गन्ने पर किसानों की जो लागत आती है उसका लाभकारी मूल्य सरकार तय करेगी और मिल मालिकों को एक तरह से मजबूर करेगी उतना मूल्य देने के लिए। तो क्या चीनी मिल मालिक अपनी चीनी का लाभकारी मूल्य तय करके देंगे या किसान के गन्ने का लाभकारी मूल्य तय करके देंगे, यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें?

श्री शरद पवार : किसानों के गन्ने की कीमत तय करने का अधिकार चीनी मिलों को नहीं दिया है। इसके लिए एक independent organisation CACP है। CACP इसकी कीमत तय करेगी। मैंने जो कहा कि 2009 और 2010 में जो बदलाव किया, इस बदलाव से 2009-2010.... In 2009-10, the FRP which was given to the farmers, was 51 per cent higher than the SMP which was paid in 2008-09; it was Rs. 28.8 per quintal higher than the SMP earlier fixed at Rs. 107.76. When we changed the system, farmers started getting better price. Last year was one of the years when sugarcane farmers got excellent price throughout India.

Technical support to Gram Panchayats

*184. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the National Commission on Farmers (NCF) has recommended training of Panchayat Members in integrated pest management, integrated nutrient supply and scientific water management;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether Government contemplates extending greater technical support to Gram Panchayats and attaching the Agricultural Universities/Institutions/Research Centres with Panchayati Raj Institutions; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. K.V. THOMAS): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The National Commission on Farmers (NCF) has recommended training of Panchayat members in integrated pest management, integrated nutrient supply, and scientific water management, as well as in new technologies such as Biotechnology and Information and Communication Technology (1CT). The Revised Draft National Policy for Fanners recommended by

NCF provides for training of one woman and man selected by each Panchayat with the help of agricultural/animal sciences universities and the persons so trained would serve as Farm Science Managers in their respective villages. The concept of farm science managers has been suitably incorporated in the National Policy for Famers, 2007 (NPF), which has been approved by Government basing on the recommendations of NCF. The NPF, 2007 also envisages support to the State Governments for devolution of functions and functionaries for empowering the Panchayats in order to implement various schemes and programmes at the grass root level; and steps to strengthen and accord centrality to Panchayats in addressing the problems of famers. NCF has not made any recommendation for attaching the Agricultural Univerisities/Institutions/Research Centres with Panchayati Raj Institutions.

Training is being imparted to famers and elected members of Panchayati Raj Institutions (PRJs) in the above mentioned areas and technologies by the Krishi Vigyan Kendras (KVKs) established in different districts in the country. The modified Scheme of'Support to State Extension Programmes for Extension Reforms' Scheme also provides for one Farmer Friend for every two census villages to facilitate famer-to-farmer extension service. Involvement of PRIs at various levels such as selection of beneficiaries, identification of Farmer Friend, selection of Farmer Teacher for Farmer Field Schools etc. is an integral part of the Suport to State Extension Programmes for Extension Reforms Scheme. Under the schemes of Rashtriya Gram Swaraj Yojana and Backward Regions Grant Fund, State Governments are being assisted for providing training and capacity building to elected representatives and functionaries of the PRIs for upgradation of their knowledge and skills.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, उसको मैंने पढ़ा है और वह बहुत ही विस्तार में है। सरकार ने काफी कुछ farmers के लिए किया है और करने जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो कुछ यहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, क्या इसके लिए इन्होंने कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है? जो सरकार के farmers के लिए प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में क्या मंत्रालय ने स्टेटों से फिगर्स मंगवाई हैं? कितनी धनराशि ग्राम पंचायतों को दी गई है और उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है या सिर्फ पेपर्स में ही हो रहा है, यह मैं जानना चाहती हूं?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, the question was, "Whether the National Commission on Farmers (NCF) has recommended training of Panchayat Members..." In the reply, I have said that on the basis of the recommendation of the National Commission on Farmers recommendation as well as the

Draft Policy, we are helping the Panchayats so that the agricultural activities can be augmented through the Panchayats.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री बाद में पूछूंगी। अभी मंत्री जी ने मेरे पहले सवाल का ही उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रही हूं कि जो इन्होंने स्कीमें चलाई हैं, उनके बारे में क्या स्टेटों से फीड बैक आया है? सर, मेरे पहले सवाल का ही जवाब नहीं आया है। सर, मैं सैकेंड सवाल बाद में पूछूंगी। इनकी स्कीमों से कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है? सर, यह तो कोई बात नहीं हुई कि मंत्री जी जवाब ही नहीं देते हैं। इतना इन्होंने बताया है। ...(**व्यवधान**)... हमने यह पूछा है, इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव प्रताप रूडी : यही बात मैं उस दिन कह रहा था कि मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : अगर आपको सेटिसफेक्टरी जवाब नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए नोटिस दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, यह तो ठीक है। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, जवाब तो दें। इनको जो रिटन में दिया जाता है, उसको ही यहां पढ़ देते हैं, जो मैं पूछ रही हूं, उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please do clarify the position.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I have got the details of the number of persons in the Panchayat institutions which have been trained. I have got a detailed list. I will pass it on to the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: The information is there. It will be made available to you.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मेरा सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार एनसीएफ के माध्यम से सहायता दे रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आप किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं? क्या ग्राम पंचायतों को सरकार यहां से आर्थिक तौर पर सहायता दे रही है, और अगर दे रही है, तो कितनी सहायता दे रही है? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना और बैकवर्ड क्षेत्र के प्लान के बारे में बताया है, लेकिन यह उससे भी पूरा होने वाला नहीं है? क्या ये और भी आर्थिक सहायता ग्राम पंचायतों को देने वाले हैं?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, according to this policy, one woman and one man is selected by each Panchayat with the help of agricultural/animal sciences universities. We also give financial

assistance under various schemes, like the RGSY so that the State Governments can help in strengthening agriculture activities through the Panchayats.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, the Minister's reply says that in every Panchayat one woman and one man is going to be selected as Farm Science Manager. This is not enough. Of course, every Panchayat has more than three or four villages. At least, five farm science managers should be trained in each village. Sir, the nation is very much in need of mechanization of our agriculture. May I know from the hon. Minister whether the farm science managers are going to give training in modern farm equipments for ploughing, seeding, weeding and harvesting. Also, I want to know from the hon. Minister...

MR. CHAIRMAN: Only one question please.

DR. K.P. RAMALINGAM: ...whether there is any programme for giving training for the manufacture of value-added agricultural products. Are you going to give any stipend to these farm science managers by Govt. of India?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, the modified scheme of support to State Extension Programmes for extension reform schemes provides one farmer front for every two census villages to facilitate farmer to farmer extension service. The involvement of Panchayat institutions at various levels such as selection of beneficiaries, identification of farmer fronts, selection of farmer teachers for farmer field schools is an integral part of the support to State Extension Programmes.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी पूछे गए सवाल का जो जवाब दिया है, उसको देखकर मुझे लगता है कि मंत्री जी ने या तो पूरी तैयारी नहीं की है या फिर वे सवाल का वास्तविक जवाब देने से हिचक रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक पंचायत में एक स्त्री और एक पुरुष को मैनेजर की नियुक्ति के लिए, प्रशिक्षित करने के बारे में सरकार ने सोचा है, विचार किया है या निर्णय किया है। माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि एक न्याय पंचायत में एवरेज चालीस से पचास हजार लोगों की जनसंख्या होती है। इस चालीस से पचास हजार लोगों की जनसंख्या के लिए एक स्त्री और एक पुरुष को आपने मैनेजर के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में कितनी पंचायतें तय की हैं और उन पंचायतों में अभी तक कितने शिक्षण कार्यक्रम हुए हैं?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I have got the State-wise details. For example, if you take Andhra Pradesh, the number of persons trained in 2007-08 is 2,42,611; in 2008-09, it is 1,56,851; in 2009-2010, it is...

MR. CHAIRMAN: Could this information be made available to hon. Members?

PROF. K. V. THOMAS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Ishwar Singh.

श्री ईश्वर सिंह : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने पंचायत के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की सिफारिश की है, उनको ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है, जो एकीकृत नाशीकीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक-पदार्थ आपूर्ति और वैज्ञानिक जन-प्रबंधन का है। पंचायत के सदस्य यहां से प्रशिक्षित होकर अपने गांवों में कृषि विज्ञान से संबंधित सेवाएं देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो भूमिहीन लोग हैं और विशेषकर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उन लोगों को इसमें पहल दी जाएगी? वे लोग ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे साधनहीन लोग हैं। क्या सरकार ऐसा विश्वास रखती है कि उनको पहल दी जाए?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, these are all under consideration. Actually, it is the State Governments which are implementing this policy. We have already given these proposals to the State Governments.

Shortage of teachers

*185. SHRI A. ELAVARASAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that our country is facing shortage of 1.2 million teachers for providing compulsory education to all children of 6-14 years of age;

(b) whether it is also a fact that the shortage is acute in rural areas;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Pursuant to the enforcement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009, the additional requirement of teachers and Head Teachers in elementary education has been estimated at 5.08 lakh and 2.44 lakh respectively. In addition, it is estimated that there are 5.23 lakh teacher vacancies in the State sector, which the State Governments are expected to fill.